MR. CHAIRMAN; So, you are doing what he wants?

SHRI SONTOSH MOHAN DEV: Yes, we are doing it.

SHRI. JAGESH DESAI- At present, the policy of the Government is to give REP licences for the goods which are imported, and alloy steel more or less is not imported. So they will not get any REP licences, and the premium on REP licences at present is 30 to 40 per cent. In view of that, if they buy the licence, the price of alloy scrap will be 30 to 40 per cent more and the price of alloy steel will go up. How is the Government going to meet this challenge? Otherwise, the whole industry will go to dogs. There should be some change in policy. What I see is, only 55,000 tonnes had been imported in...,

MR. CHAIRMAN: What is your question? Is it whether they will change their policy? ...

SHRI JAGESH DESAI: Only one lakh tonnes they are going to import. How are they going to meet this challenge?

SHRI SONTOSH MOHAN DEV: It is a fact that we do give REP licence for alloy steel. And it is not a fact that they are not in a position to reap the profits from REP licence because in the past, one million tonne was brought into the country through REP. But the hon. Member is very much correct that the cost will go up by 35 to 40 per cent, and even then, the industry will have to bear it; it will escalate the price. That is why we are asking that zero-based tax should be included, and I hope I get the blessings of the full House.

SHRI SUNIL BASU RAY: I want to know what is the total demand in the country and what is the internal availability. Secondly, I want to know: in view of the shortage of scrap prevailing in the country, will the import restriction, that has been imposed, be lifted or not? Thirdly, I want to know what is the total amount of imports that the private importers are importing.

SHRI SONTOSH MOHAN DEV; For 1991-92, the demand is 70 lakh tonnes. The scrap available in the country is 30 lakh tonnes and the sponge iron availability is 10 lakh tonn;s. We have been able to import only 55,000 tonnes. Another 1,17,000 is in the pipeline. As I said, with the allocation of foreign exchange, we will be able *to* meet the demand to the extent of 10 to 12 per cent only. I don't have the figures with me as to what has been brought by REP as it is not monitored by my Ministry; it is monitored by the Finance Ministry.

Adverse impact on Monsoon based crops

*84. SHRI SOM PAL:†
SHRI CHIMANBHAI MEHTA:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what is the likely adverse impact on monsoon-based agricultural crops due to paucity of rains in certain parts of the country; and

(b) whether Government have worked out necessary measures in all directions i.e. mitigating hardships to agriculturists, agricultural labourers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): (a) Till recently, parts of Uttar Pradesh, Bihar, Haryana and Rajasthan and experienced deficit rainfall resulting in poor sowings I transplantation of crops; crops already sown also experienced moisture stress on account of long dry spells.

(b) Yes, Sir. The situation is being closely monitored by the Centre and, apart from arranging additional supplies of die-sel and other inputs, the State Governments have been advised and helped to draw and implement crop contingency plans and other relief measures to be funded out of the Calamity Relief Fund.

श्री सोम पाल : सभापति महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी से जो सवाल मैं पूछना चाहता हूं, वैसे तो यह वर्षा से धूल चुका है।

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Som Pai.

पर सौभाग्य से चाहे देर में ही सही इस वर्षा से किसान को कुछ राहत मिली। गत सप्ताह मैं व्यक्तिगत रूप से हरियाणा के जिला सिरसा और झज्जर बेल्ट में गया था जो हमारे माननीय डा. बलराम जाखड़ जी के अपने गांव के आसपास के क्षेत्र हैं। यह व्यक्तिगत रूप से जानते हैं इन क्षेत्रों को करनाल, में, कुरुक्षेत्र में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े इलाके में तीन फसलों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। एक तो धान की फसल को सिरसा जिले में नुकसान पहुंचा है। मैंने देखा है 60 परसेंट से ज्यादा धान की फसल पूर्णत नष्ट हो चुकी है सूखे के कारण। करनाल में भी लगभग 40 परसेंट फसल का नुकसान हुआ है और यह बात वहां के कृषि विभाग के अधिकारी भी मानते हैं। इसी तरह से हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग में भी यही स्थिति है। मुझे आशंका है कि धान जो एक मुख्य खाद्य फसल है उसका उत्पादन निश्चित रूप से काफी मात्रा में इस वर्ष कम होगा।

दूसरे हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में गन्ने की फसल को भी बहुत नुकसान हुआ है दो प्रकार से। एक तो पानी की कमी से और दूसरे जब पानी की कमी होती है तो सूखा पड़ता है और उस समय एक कीड़ा इस प्रकार का होता है जो ईख में लग जाता है जिसे हमारी देहाती भाषा में कंसवा कहते हैं। इस कीड़े से फसल का बढ़ना बंद हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप चीनी के उत्पादन में भी कमी होने वाली है। तीसरे ऐसी ही फसल चारे की है जिसके कारण पशुओं को कठिनाई पड़ सकती है। इन तीनों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार क्या उपाय करने जा रही है यह मैं जानना चाहता हूं।

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़): माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो कहा आज से कुछ दिन पहले चिंता का विषय जरूर था। यह भी सही है कि कुछ हिस्सों को छोड़ कर धान की फसल में नुकसान का अंदेशा आज है। हरियाणा में क्योंकि काफी देरी से बरसात हुई, ज्यादा बिजली से पानी देने से भी यह फसल नहीं बच पाई क्योंकि सूखा काफी लम्बा था। इसी तरह यूपी में भी चिंता का विषय था क्योंकि वहां भी बरसात लेट आई। लेकिन इन चीजों के होने के बावजूद मैं आश्वासन दे सकता हूं माननीय सदस्य को कि चिंता का विषय अब नहीं रहा। जो फसल अब नहीं रही, जैसा आप कहते हैं कि कहीं 60 परसेंट नुकसान हुआ और कहीं 40 परसेंट नुकसान हुआ है लेकिन यू.पी. जैसे क्षेत्र में अब 80 प्रतिशत काम ठीक हो जाएगा। मैं अभी अभी कानपुर, लखनऊ वगैरा से होकर आया हूं, अभी भी वहां पर धान की रुपाई चल रही है और इस तरीके से हम पूर्णरूपेण काम कर लेंगे। मेज का काम भी चल रहा है और दूसरे काम भी हो रहे हैं। जो भी नुकसान हुआ है उसमें हम आयल सीड्स लगा कर उसको पूरा कर लेंगे। इसमें किसानों का हित होगा और देश के लिए भी काम ठीक हो जाएगा।

चारे का जो मसला है वह भी अब बरसात होने के कारण बिलकुल हमारे सामने पेश नहीं आएगा। हमारा काम फिर से ठीक प्रकार से चलेगा। हमने स्टेट्स गवर्नमेंट्स को लिखा हुआ है और हम तैयारी भी रखे हुए हैं। हमेशा उनसे हमारा डिपार्टमेंट बातचीत करता रहता है कि वे तैयार रहें और तैयार रह कर जो भी स्थिति हमारे सामने उपस्थित हो उसका पूरा मुकाबला किया जाय। इसलिए चिन्ता का विषय अब नहीं रहा।

श्री सभापति : गन्ने पर जो रोग लगा है उसके बारे में भी बता दीजिये।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : गुजरात सरकार ने अपने कुछ जिलों में स्केयरसीटी डिक्लेयर कर दी है, उसके बारे में आपका क्या कहना है... (व्यवधान)

श्री बलराम जाखड़ : बाद में बताऊंगा। सारी जगह ऐसा नहीं है। कुछ तो फर्क पड़ता ही है।

श्री सभापति : गन्ने पर जो रोग लगने की बात उन्होंने कही है उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा।

श्री बलराम जाखड़ : गन्ने के विषय में नुकसान की रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई है।

श्री सभापति : उन्होंने बताया है कि गन्ने पर रोग लगा हुआ है ।

श्री बलराम जाखड़ : मेरे पास ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है । हमारे इलाके फिरोजपुर, गंगानगर और सिरसा का जिक्र उन्होंने किया है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : आपके इलाके में इनका जाना खतरनाक है ।

श्री बलराम जाखड़ : बड़ा खतरा है, क्या बतायें, लेकिन हमारे मित्र हैं । हम खतरे का भी स्वागत कर लेंगे । ऐसा करने की क्षमता हम में है । वहां पर कपास फसल अच्छी है । अभीअभी एयर स्प्रे का बंदोबस्त हमने किया है । शायद आप भी उसका फायदा उठा सकते हैं, गन्ने के लिये भी उसका फायदा हो सकता है । लेकिन मेरे पास गन्ने में बीमारी के प्रकोप की रिपोर्ट नहीं आई है ।

श्री सोमपाल : सभापति महोदय, मंत्री जी ने बताया है कि अब वर्षा हो गई है । लेकिन जैसा कि हिन्दी के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास ने लिखा है– 'का वर्षा जब कृषि सुखाने' । इसके पूर्व फसल को काफी नुक्सान हो चुका है । इसलिये मेरा कहना है कि खाद्यान्न में कमी होगी और खासतौर से धान की पूर्ति में कमी होगी । दूसरा मेरा पूरक प्रश्न यह है कि गन्ने की फसल पर कीड़ा लगने के कारण बहुत नुक्सान हुआ है । पहले भी इस संबंध में कृषि मंत्री जी ने एक वक्तव्य सदन में दिया था और कुछ सदस्यों के पूछने पर स्पष्टीकरण के तौर पर यह बात बताई थी कि गन्ने पर जो कीड़ा लग रहा है उसके लिये प्राय: राज्य सरकारें एयर स करती है, हवाई जहाज से दवाई का स्प्रे किया जाता है । यह मांग सदन में पहले भी रखी गई थी और मैंने भी कहा था । इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को मैंने एक पत्र भी लिखा था, लेकिन एयर स्प्रे अभी तक नहीं हुआ । इसलिये क्या इस संबंध में राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार निर्देश देगी ? मैं यह भी कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार की तरफ मेरी जानकारी के अनुसार कुछ अनुदान राज्य सरकारों को इस विषय में दिया जाता है । 1986 में इसी प्रकार की महामारी के समय लगभग सात करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश की सरकार को दिया गया था । क्या इसी प्रकार का अनुदान देकर उन्हें निर्देश दिया जायेगा कि हवाई जहाज से स्प्रे किया जाय ताकि इस बीमारी की रोकथाम की जा सके ?

श्री बलराम जाखड़ : गन्ने के बड़े होने के पश्चात् हाथ से स्प्रे होना मुश्किल है । इसलिये आवश्यक है कि उसका एयर से स्प्रे किया जाय । मेरे पास पंजाब से मांग आई थी । उसका मैंने पीछा किया और मेरे ख्याल से वह मंजूर भी हो जायेगा । उसके लिए 50 प्रतिशत का आपस में बंटवारा है । अगर उत्तर प्रदेश से भी इस किस्म की मांग आती तो हम उसको भी जरूर देखते । मेरे ध्यान में यह बात नहीं आई है और अगर आती तो मैं जरूर उसका भी पीछा करता और उनको भी इसका फायदा देने की कोशिश की जाती जो दूसरे इलाकों के लिये दी जाती है । बाकी आपने धान की कमी होने की बात कही है । मेरे ख्याल से धान में ज्यादा कमी नहीं होगी, लेकिन अगर धान में कमी होती है तो दूसरी चीजों जैसे मेज, बाजरा और ज्वार से हम उसकी पूर्ति कर लेंगे । वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं अभी हमारे पास गल्ले का स्टाक बहुत है । अभी हमने इससे 5 लाख टन गल्ला धान का भेजने का प्रावधान किया है और हो सकता है कि शायद इसके पश्चात् फसल ठीक रहे तो और भी करेंगे ।

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: Sir some relief is felt because of the answer of the hon. Minister. But besides this, it he provides some more information, it will be good. I would like to know, what will be the actual quantum of shortfall in foodgrains production?

I can understand, rouga estimate can be given, but a provision can be made if we have stocks of last year. Already the prices

are gtyitig up. As a precautionary measure the hon. Minister can assure the people oa litis. It is also said that on the *lan*d where foodgrains sowing is not possible, alternative crops and oilseed crops would be-planted. Now that the season is over in soma pacts, I do not know whether it will be possible *to* do it in all soils. you can do it where irrigation is being done, but not everywhere. So, what are the other alternative crops that can be planted?

SHRI BALRAM JAKHAR: I can assure the hon. Member that there is no paucity of foodgrains. We have got 19 million tonnes in stock. If there had been any shortfall, anticipated shortfall, we would not have allowed 5 lakh tonnes to be exported. Not only that, about IO lakh tonnes of wheat also we are going to export. So, we are in a very comfortable position. We are taking care on that score. Otherwise, for oilseeds it is the time for sowing. Not only that, we can reap the harvest and go on for wheat cultivation. That is how we can do.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: Mr. Chairman, Sir, there are two aspects of this question. One is about drought and the other is about floods. In some parts of the country there has been a heavy rainfall. Especially, in some parts of Maharashtra there has been a heavy rainfall in the recent past and the worst tragedy occurred in village Mowad. The entire village has been washed away and 1500 lipes have been lost Mowad village Is in Vidarbha which is the erstvhfle con-stitueitcy of Shri Narasimfta Rao. What is the toss to the cash crops, to the Khariff crops due to heavy floods, rising of the Wardha river and heavy rainfall?

MR. CHAIRMAN: The question is on paucity of rains and not extra rain. Tiese are two different things. No. no, I cannot allow. *{Interruptions').* You read the whole question. yes, Mr. Satya Prakash Malaviya.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: The question is like this.

MR. CHAIRMAN: No, no. I have seen the question and I have decided that you cannot *pat* the question on floods. *(Interruptions-* 'i. I have decided it,

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : सभापति महोदय, देश के उत्तरी हिस्सों से मानसून 18–20 जून तक आ जाता है। लेकिन इस साल देर से आया और इसके कारण वर्षा देर से शुरू हुई। इसलिये विशेषकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Please sit down. I will not permit. *{Interruptions').* Nothing will go on record.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: *

MR. CHAIRMAN: I am not permitting. Please sit down. Nothing will go on record.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV:

MR. CHAIRMAN: Yes, this is it. Nothing will go on record. You can protest but I have my own way of seeing things. The question is on scarcity. If I allow it every oher thing will come in.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: *

MR. CHAIRMAN: You ask about scarcity. Yes, Mr. Malaviya.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : माननीय सभापति जी, देश के उत्तरी हिस्सों पर मानसून 18–20 जून तक आ जाता है । इस वर्ष क्योंकि मानसून देर से आया इसलिये वर्षा भी देर से हुई । इसके कारण विशेषकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में बुआई देर से हुई और फसल का नुकसान हुआ । मंत्री जी ने अभी अपने उत्तर में बताया कि इन राज्यों को कैलामिटी रिलीफ फंड से राहत उपाय लागू करने के लिये सहायता दी गई है । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन चार राज्यों, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली को अलग-अलग दैवी आपदा राहत कोष से अब तक कितनी सहायता दी गई है और अगर अभी तक नहीं दी गई है तो कितनी सहायता देने का केन्द्र सरकार का विचार है ?

*Not recorded.

श्री बलराम जाखड़ : महामना, इस प्रकार की आवश्यकता ही नहीं रहेगी जिसमें कि उसका उपयोग किया जाए क्योंकि 9वें फाइनेंस कमीशन की डायरेक्शन यह स्टेट्स और सेंटर ने बैठ कर तय मंजूर कर लिया था कि जो पैसा सेंटर देता है वह स्टेट्स को सीधे ही दे दिया जाए और वही अपना काम निर्धारित करे कि कहां कितना मुआवजा देना है और कहां कितना नुकसान हुआ है। तो अलाहिदा-अलाहिदा स्टेट्स का अलाहिदा है मैं आपको आंकड़े दे सकता हूं। उत्तर प्रदेश का शायद 90 करोड़ है और पंजाब का 24 करोड़ है। इस प्रकार से मुझे जबानी याद नहीं है। If you want I can send you all the details. I gave them in my reply to the discussion on the drought and flood situation here. I replied fully to thet. चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने दो किश्तें पहले ही दे दी हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : चिंता इसलिए है कि इस साल नकसान ज्यादा हुआ है।

श्री बलराम जाखड़ : नहीं, नहीं। नुकसान नहीं होगा। सब ठीक हो जाएगा। अब इस तरह की बात नहीं बनेगी जैसे कि गड़बड़ थी। दो किश्तें पहले हमने भेजी हैं। अगर स्टेट्स को आवश्यकता हो तो तीसरी भी मंगा सकते हैं और ज्यादा आवश्यकता हो तो चौथी किश्त भी हम दे सकते हैं।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : सभापति महोदय, मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा, सरकार को शायद यह पता होगा कि गुजरात में दो ही डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर आज दिन तक बारिश नहीं हुई है। एक डिस्ट्रिक्ट को तो कल ही सरकार ने सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। वहां पर पीने के लिए पानी की बहुत बड़ी तकलीफ हो गई है। किसान परेशान है। इस वजह से क्या केन्द्रीय सरकार इन डिस्ट्रिक्ट में अपने यहां से एक टीम भेज कर सर्वे कराएगी। मैं पीने के पानी के लिए नहीं कहना चाहता लेकिन विशेष रूप से किसानों के लिए जिनकी फसल बारिश न होने की वजह से, सूखा पड़ने के कारण खत्म हो गई है, क्या उनके लिए आप कोई सुविधा करेंगे ?

श्री बलराम जाखड़ : महामना, अगर माननीय सदस्य ध्यान देते, जो मैंने पहले प्रश्न का उत्तर दिया है, उसी में इसका भी उत्तर निहित है। जो पैसा हमने कैलेमिटी रिलीफ फण्ड के माध्यम से देना था, वह पहले से स्टेट्स के पास पड़ा है। उनके पास पैसा है। और आवश्यकता हो तो अगली किश्त भी हम से मंगवा सकते हैं। यह काम स्टेट्स का है इसलिए वही करेंगे।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : आप टीम भेज कर सर्वे करा लीजिए।

श्री बलराम जाखड़ : हमारा वास्ता नहीं रहा। टीम भेजने का वक्त पुराना था। आपने सुना नहीं, जब सूखे पर यहां बहस हुई थी तो उस समय मैंने क्लीयर कर दिया था कि अब टीम भेजने की आवश्यकता नहीं रही है। टीम तब भेजते थे जब पैसा सेंटर देता था। स्टेट्स ने यह कहा कि पैसा हमारा है, आप कौन चौधरी होते हैं, यह हमने देखना है कि हमने पैसा कहां लगाना है, यह फैसला हम करेंगे कि हमने पैसा कहां लगाना है। यह बात सेंटर ने मान ली कि हां आपका पैसा है, आप अपना पैसा ले लीजिए। तीन चौथाई हम देते हैं और एक चौथाई वह देते हैं।

श्री राम नरेश यादव : मान्यवर, उत्तर प्रदेश तो पिछले दिनों सूखे से बहुत तबाह रहा है। यहां तक स्थिति थी कि जो धान की रोपाई हो रही है, अभी भी कानपुर में कुछ जगह रोपाई चल रही है ....

श्री सभापति : आप प्रश्न कर लीजिए

श्री राम नरेश यादव : मैं प्रश्न कर रहा हूं । जो धान की सीडलिंग होती है, जिससे धान की रोपाई की जाती है, वह भी सूख गई है इसकी प्रदेश के किसी हिस्से में आवश्यकता ही नहीं रही । किसान तो उससे महरूम हो गया है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि पिछले दिनों जो सूखा न हुआ है, प्रदेश की सरकार की जो । पोर्ट आई है उस रिपोर्ट के आधार पर क्या माननीय मंत्री जी यह बता सकते हैं कि खरीफ की कितनी फसल के नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है और जो मोटे अनाज होते थे, उनकी क्षति का कितना अनुमान लगाया गया है। अगर कोई रिपोर्ट नहीं आई है तो क्या माननीय मंत्री जी प्रदेश की सरकार से इस संबंध में कोई रिपोर्ट मंगवायेंगे । दूसरी बात यह है इसके साथ-साथ, क्योंकि किसान का सारा खाने का सामान घर से बाहर चला गया, उसने बोआई कर दी, उसके पास कुछ खाने के लिए बचा ही नहीं । अब वह रबी की बोआई कैसे करेगा ? इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे से जो यह सारी तबाही हुई है अगली आने वाली रबी की फसल की बोआई के लिए केन्द्र सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है, प्रदेश सरकार को क्या निर्देश देने जा रही है ? जिस किसी तरह से भी हो, जिन सारी चीजों की कमी होगी, बीज की कमी होगी, उसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार क्या कर रही है ?

श्री बलराम जाखड़ : सभापति जी, जहां तक माननीय सदस्य का यह कहना है कि धान की रोपाई नहीं हो सकती । अब देखने और सुनने में बड़ा अंतर आ जाता है। मैं तो स्वयं देख कर आया हूं।

श्री राम नरेश यादव: मैं अभी चार दिनों में गया था देवरिया गया था, गोरखपुर, आजमगढ़ और लखनऊ गया था । इन सारी जगहों पर घूम कर आया हूं । मैंने देखा है और अपने जिले में भी देखा है **(व्यवधान)**

श्री बलराम जाखड़ : मैं स्वयं देख कर आया हूं । धान लगता हुआ मैंने देखा है, लोगों को धान लगाते हुए देखा है। लेकिन जहां नहीं है वहां हमने उत्तर प्रदेश सरकार को बीज चाहिए तो बीज दी, खाद चाहिए तो खाद दी और जो हमसे सहायता हो सकती है– और हमने पर्णरूपेण आदेश दिये हुए हैं कि जो आपको साधन चाहिए उनको जुटाना आपका परम कर्तव्य भी है और उसको निभाना भी आपका धर्म है, आप करिए, जो हमसे सहायता चाहते हैं हम देंगे ।

Procedure adopted by Railway Claims Tribunal or paying compensation to kith and kin of accident victims

*85. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) what is the procedure adoped by Railway Claims Tribunal in deciding the compensation claims by the kith and kin of a victim in any Railway accident;

(b) what is the minimum time taken by the Tribunal in deciding a claim;

(c) whether all the claims have been cleared by the Tribunal which came before it during the last three years;

(d) if not, the details thereof; and

(e) by when all these claims are likely to be cleared?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARIUN): (a) The procedure is prescribed in the Railway Claims Tribunal (Procedure) Rules, 1989.

(b) Three months.

(c) No, Sir.

(d) Of the 1559 cases filed before the Tribunal since its inception in November 1989, 1069 cases have already been adjudicated.

(e) No accurate estimate can be given